



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2004/ज्येष्ठ 3, 1926

No. 110]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2004/JYAISTHA 3, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2004

जाँच शुरूआत ( मध्यावधि समीक्षा )

विषय.—रूस, चीन और यूक्रेन से कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स के आयातों पर लगाये गए पाटनरोधी शुल्क के बारे में मध्यावधि समीक्षा शुरू करना।

सं. 15/6/2004-डीजीएडी.— निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए रूस, चीन और यूक्रेन (जिन्हें आगे सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित उपशीर्ष 7206.90, 7207.19 और 7207.20 के अंतर्गत आने वाले कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स (जिन्हें आगे सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और जांच परिणाम 01 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 31/1/99 के तहत प्रकाशित किए गए थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 01 जून, 2001 को प्रकाशित किए और सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 26 जून, 2001 को लगाया गया था।

## 1. विचाराधीन उत्पाद

कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स हैं जिनका व्यास आई एस विनिर्देशन अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन के अनुरूप 70 मिमी-250 मिमी है, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 की उपशीर्ष 7206.90, 7207.19 और 7207.20 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

## 2. जांच शुरूआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रूस, चीन और यूक्रेन से कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए 09 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० 31/1/99 के तहत सार्वजनिक सूचना जारी की और 01 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाना उचित समझा। निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के प्रावधान के तहत इस स्तर पर संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित होगा। मै० महाराष्ट्र सीमलेस स्टील ने रूस, चीन और यूक्रेन से कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स पर पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

## 3. प्रक्रिया

01 जून, 2001 की अधिसूचना सं० 31/1/99 के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और 26 जून, 2001 को लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का निर्यात, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार रूस, चीन और यूक्रेन से कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की जरूरत और इस बात की समीक्षा करने के लिए एतद्वारा जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. इस समीक्षा में 01 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 31/1/99 और 01 जून, 2004 के परवर्ती अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल हैं।

5. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 तक की है।

## 6. सूचना प्रस्तुत करना

सम्बद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में सम्बन्धित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से पत्र लिखे जा रहे हैं कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करें और अपने विचारों से अवगत कराएँ :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकती है।

## 7. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों से पहले पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

## 8. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अंगीकृत अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2004

Initiation (Mid Term Review)

**Subject.—Initiation of Mid Term Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds from Russia, China and Ukraine.**

**No. 15/6/2004-DGAD.—** The Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Russia, China and Ukraine (hereinafter referred to as subject countries) falling

under Sub-heading 7206.90, 7207.19 and 7207.20 and the findings were published vide Notification no. 31/1/99 dated 1<sup>st</sup> December, 2000. The Designated Authority came out with final findings on 1<sup>st</sup> June, 2001 and definitive anti dumping duty was imposed by Customs on 26<sup>th</sup> June, 2001.

### **1. Product Under Consideration**

Product under consideration is certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds having 70 mm – 250 mm dia conforming to IS specification or any other international specification which is classified under sub-head 7206.90, 7207.19 and 7207.20 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The Classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations.

### **2. Initiation**

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Rules made there under require the Authority to review, from time to time, the need for continuance of Anti Dumping Duty. The Designated Authority issued public notice vide Notification No. 31/1/99 dated 9<sup>th</sup> December, 1999 for initiation of anti dumping investigation concerning certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds originating in or exported from Russia, China and Ukraine and considered appropriate to impose Anti Dumping Duty vide Notification dated 1<sup>st</sup> June, 2001. The Designated Authority now considers that the mid term review of the Anti Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995. M/s Maharashtra Seamless Steel has submitted a representation for withdrawal of Anti Dumping Duty on certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds originating in or exported from Russia, China and Ukraine.

### **3. Procedure**

Having decided to review the final findings notified vide No 31/1/99 dated 1<sup>st</sup> June, 2001 and final duty imposed on 26<sup>th</sup> June, 2001, the Authority hereby initiates investigations to review the need for the continued imposition of anti-dumping duty and whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or

recurrence of dumping and injury on imports of certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds originating in or exported from Russia, China and Ukraine in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

4. The review covers all aspects of Notification No.31/1/99 dated 1<sup>st</sup> December, 2000 and subsequent final findings dated 1<sup>st</sup> June, 2001.

5. The period of investigation for the purpose of the present review is 1<sup>st</sup> January, 2003 to 31<sup>st</sup> December, 2003.

#### **6. Submission of Information:**

The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **7. Time Limit**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**8. Inspection of Public File:**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Addl. Secy. & Designated Authority